



अधिकतम : 26° C
न्यूनतम : 16° C

अबरे सुपाता नही, छापवा है

शाह टाइम्स

बरेली, मंगलवार 7 अप्रैल 2026 बरेली संस्करण: वर्ष 23 अंक 126 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com

बैसाख कृष्ण पक्ष 5 विक्रमी सम्वत् 2083

18 शबाल 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वारी, मुतादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



सत्ता नहीं, संस्कार की है भाजपा की विकास यात्रा: योगी



ऑरेंज कैप की दौड़ में समीर रिजवी सबसे आगे खेल टाइम्स



राजनीति का नया भूगोल लोकसभा विस्तार व नारी शक्ति का नया उदय सम्पादकीय



युद्ध कई साल चला, तो भी नहीं होगी मिसाइलों की कमी: ईरान

ईरान ने दुकराया युद्धविराम का प्रस्ताव, हमले जारी रहने तक नहीं होगी सीधी बातचीत

तेहरान, वार्ता
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनियां मिल रही हैं, तो दूसरी ओर ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बना रहा है।
इस बीच, ईरान ने सोमवार को कहा कि उसने मध्यस्थों की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों पर अपना जवाब तैयार कर लिया है। हालांकि, उसने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका व इजरायल हमले तेज करते रहेंगे, वह सीधी वार्ता में शामिल नहीं होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव अत्यधिक मांगों वाला है। हमने अपनी मांगों का एक



अलग सेट तैयार कर लिया है और उसे औपचारिक रूप दे दिया है। इस संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस्फाहन में पायलट बचाव अभियान केवल एक छल-कपट था, जिसका मकसद ईरान के संवर्धित यूरेनियम को जबरन लेना था। यह युद्धविराम

■ अस्थायी युद्धविराम के बदले होर्मुज स्ट्रेट खोलने से किया इन्कार
तेल अरबी/तेहरान। इजरायल ने सोमवार को ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर फिर से मिसाइल हमला किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, जो ईरान और कतर के बीच फैली हुई है।
इससे पहले इजरायल ने 18 मार्च को भी इस गैस फील्ड पर हमला किया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा

■ ट्रम्प ने यहां अटैक करने से मना किया था, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास धमका
था कि उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। तब ट्रम्प ने ये भी कहा था कि इस तरह के और हमले नहीं

होने चाहिए। वहीं सोमवार को जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास भी धमकाओं की आवाज सुनी गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल के हमले बढ़ें, तो वह ग्लोबल सप्लाय चैन को ठप कर देगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बग्राई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर तेहरान अपनी पूरी ताकत से अपने देश को रक्षा करेगा।

हमले में IRGC के खुफिया एजेंसी के प्रमुख की मौत
तेहरान। आईआरजीसी के खुफिया संगठन के प्रमुख मेजर जनरल मजीद खार्दमी की अमेरिका-इजरायल के हमले में मौत हो गई है। आईआरजीसी ने सोमवार को एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आईआरजीसी के खुफिया संगठन के प्रमुख मजीद खार्दमी की सोमवार सुबह अमेरिकी-इजरायली हमले में मौत हो गई।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली विस की सुरक्षा में चूक, बैरियर तोड़कर घुसी कार
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा कैम्पस में सोमवार दोपहर को सुरक्षा में चूक हुई। दोपहर करीब 2 बजे यूपी नंबर की कार वीआईपी एंटी वाला गेट नंबर-2 को बैरिकांडिंग तोड़कर अंदर घुसी। कार ड्राइवर ने नकाब पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर गया और पोर्च के पास गुलदस्ता रखकर कार समेत मौके से फरार हो गया। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। घटना के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। गेट नंबर 2 पर अब सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक उत्तर प्रदेश के पौलीभौत का रहने वाला सरबजीत है।
दो जहाज जल्द 60 हजार टन एलपीजी लेकर पहुंचेंगे भारत
नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद भारत के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बताया कि एलपीजी (रसाई गैस) लेकर आ रहे भारत के दो जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और जल्द भारत पहुंचेंगे। इन जहाजों के नाम ग्रीन सान्बी और ग्रीन आशा हैं। इनमें कुल मिलाकर 60 हजार टन से ज्यादा गैस है। ग्रीन सान्बी 7 अप्रैल और ग्रीन आशा 9 अप्रैल तक भारत पहुंच सकते हैं। सरकार के मुताबिक, दोनों जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें भारतीय नाविक भी सवार हैं। एक जहाज में करीब 46 हजार टन और दूसरे में लगभग 15 हजार टन गैस है।
ब्रह्मोस प्रोजेक्ट से जुड़े अलेक्जेंडर लियोनोव की मौत
पारको। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े रूस के प्रमुख वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे रूस के प्रमुख मिसाइल डिजाइनरों में शामिल थे। लियोनोव एनपीओ मोशिनोवोएनियका के सीईओ और चीफ डिजाइनर थे, जो भारत-रूस की ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख साझेदार है। उन्हें उन्नत मिसाइल तकनीक के विकास के लिए जाना जाता था। उन्होंने जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया। उन्होंने प्रेनित, वल्कन और वास्टिनन जैसे मिसाइल और कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स के विकास में भी भूमिका निभाई थी।

बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट गंभीर मतदाता सूची अपडेट करने के लिए तय की एक दिन की समयसीमा

टिब्यूनल को भी निर्देश जारी किए
शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची अपडेट के लिए एक दिन की समयसीमा तय की है।
श्रीधर कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) न्यायाधिकरणों को दस्तावेजों को फिर से देखने का आदेश दिया है। श्रीधर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे पूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को फिर से देखें, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की ओर से दिए गए कारण भी शामिल हैं, ताकि किसी भी तरह के संदेह को दूर किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने उनसे अनुरोध किया है कि पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई की जाए। निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम

मालदा घटना: हाईकोर्ट सीजे का फोन न उठाने पर मुख्य सचिव को लगाई फटकार, कहा- माफी मांगो
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मालदा के मामले से जुड़े दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया और कहा कि स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार अल्टिमाटम 142 का इस्तेमाल करते हुए मालदा की घटना से जुड़े सभी मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी है।
बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के दावों और आपत्तियों पर न्यायिक अधिकारियों ने अब तक 59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया है। आयोग ने कोर्ट को बताया कि बाकी बचे दावों और आपत्तियों पर दिन में फैंसला किया जाएगा, ताकि सभी मामलों का निपटारा समय पर हो सके। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेष मतदाताओं की पूरक सूची आज रात प्रकाशित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र का हवाला दिया, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज चिस्टिस ने भेजा था। इस पत्र में बताया गया कि हटाए गए 60

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज

शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। 190 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सभापति द्वारा खारिज किया गया। विपक्ष ने उन पर मतदाता सूची में हेरफेर और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप लगाए थे।
टीएमसी के नेतृत्व में विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया था, लेकिन यह बट सत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची से नाम हटाने, चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। सीईसी को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान महाभियोग की कठिन प्रक्रिया (विशेष बहुमत) की आवश्यकता होती है, जो भारत में अब तक किसी सीईसी के



190 से अधिक सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर
इतिहास में पहली बार आया था सीईसी को हटाने का प्रस्ताव
खिलाफ नहीं हुई। यह भारत के संसदीय इतिहास में किसी सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की पहली कोशिश थी। सुओं के मुताबिक इस पहल की शुरुआत टीएमसी ने की थी। पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सहमत किया। इससे पहले

बागपत में तोतों के तीन तस्कर अरेस्ट

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। पुलिस और एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास से 170 दुर्लभ प्रजाति के तोते बरामद किए हैं। इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके दो साथी मौके से फरार हो गए।
यह कार्रवाई मवीकला टोल के निकट एक सड़क गाड़ी को रोकने के बाद की गई। गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें सात प्लास्टिक के बक्से मिले, जिनमें तोतों को तस्करों के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस और एनिमल



वेल्फेयर एसोसिएशन की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने बताया कि उन्हें तोतों की तस्करों के संबंध में सूचना मिली थी। इसके बाद एक जाल बिछाया गया और बागपत पुलिस से संपर्क किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान कन्नौज निवासी खुर्शीद, मोहसिन और राजा के रूप में हुई है। फरार हुए दो साथियों के नाम शमीम और

मुजफ्फरनगर में तीन को फांसी की सजा सुनाई

शाह टाइम्स ब्यूरो
कोर्ट ने अधिवक्ता के दोषियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के सनसनीखेज कांड अधिवक्ता समीर सैफी अपहरण हत्या और लाश को छुपाने के मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस कांड के सहयोगी नौकर को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसमें दस लाख रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है। इस फैसले के बाद पीडित परिवार ने कोर्ट का शुक्रिया ही नहीं किया, राहत की सांस भी ली है।
बता दें कि 15 अक्टूबर 2019 को अधिवक्ता समीर सैफी अचानक सड़क पर स्थितियों में लापता हो गए थे। काफी समय बाद भी जब समीर सैफी घर नहीं लौटे, तो परिवार को चिंता ने उन्हें थाने तक पहुंचा दिया था। अधिवक्ता के संबंध में नगर कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई, जहां परिवार के लोग पुलिस समीर सैफी की तलाश में जुट गए थे। 19 अक्टूबर को अधिवक्ता समीर सैफी का शव भोपा थाना क्षेत्र के गांव सीकरी के जंगल में दबा हुआ मिला था। अधिवक्ता का शव मिलने के बाद यह मामला पूरी तरह सनसनीखेज बन गया था और इस मामले को खानबीन के दौरान पुलिस ने पाया

सोहराब बताए गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि ये तोते राजस्थान से गाजियाबाद के लोनी ले जाए जा रहे थे। तस्कर एक निजी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। सूचना के आधार पर ही इन आरोपियों को पकड़ा गया। फिलहाल, बागपत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भाजपा के स्थापना दिवस पर राष्ट्र प्रथम का संकल्प

शाह टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं और 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को दोहराया।
श्री नवीन ने इस मौके पर भाजपा मुख्यालय पर कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए 'राष्ट्र सर्वोपरि' के संकल्प को दोहराया और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी



'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होने की जरूरत: पीएम मोदी
के सिद्धांत पर चलते हुए समाज सेवा में अग्रणी रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निरवस्था सेवा, समर्पण और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को पराहना करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों ने पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने उन अनगिनत कार्यकर्ताओं को भी याद किया,

जिनके त्याग और बलिदान ने पार्टी के विकास को आकार दिया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी के रूप में खड़ी है, जो लोगों की भलाई को अपने दृष्टिकोण के केंद्र में रखती है। यह केंद्र और विभिन्न राज्यों में हमारे काम में भी झलकता है। भाजपा एक 'विकसित भारत' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक संकल्प इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता रहे और भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पीडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से प्रेरित भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प है।

संयुक्त अभियान ही प्राथमिक रणनीति होगी: जिलाधिकारी

डीएम ने की जनपद में अवैध खनन, परिवहन व ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ट्रैक्टर आडक फोर्स के साथ की बैठक

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध बागपत प्रशासन ने कड़ी सख्त अग्रीवा है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल के की अध्यक्षता में आयोजित हुई ट्रैक्टर फोर्स को बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप 'सीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए अथ हर स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने निगरानी, तकनीक और समयवश के लिए एक इंटीग्रेटेड मॉडल लागू कर दिया है, जिसमें अवैध गति, विधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है।



दरनाली स्थलों को पहचान कर वहां विधि निर्माण और लगातार चिकित्सा अभियान चलाया जाएगा। अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए अब 24x7 निगरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। गति रोकने के लिए सख्त नियंत्रण रखकर खनन क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर नजर रखेंगी। हर स्तर से रिपोर्टिंग को स्पष्ट व्यवस्था

खनन स्थलों और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्विलांस और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। डिजिटल मॉनिटरिंग से अवैध गतिविधियों को तुरंत पहचान कर कार्रवाई संभव हो रही है। थप हो रहे संपन्न और अनैतिकता पैदा करने के माध्यम से शिकायतों का स्वतंत्र निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में वर्तमान में केवल 5 खनन पर ही स्विकृत हैं और खनन कार्य इन्हों निर्मित सीमाओं के भीतर किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अनैतिक खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा गांव में खनन कार्य नहीं होगा, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। ट्रैक्टर फोर्स समिति को विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो अवैध खनन और परिवहन के मामलों में तत्काल कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने

नियमों का उल्लंघन कर रही तीन बसों को किया सीज

पर ही अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए अधिकारियों ने स्पष्ट किया



शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। दिल्ली-सहारनपूर रोड पर परिवहन विभाग ने सख्त बर्तन अधिमान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर रही तीन बसों को सीज कर दिया गया। अधिमान का नवतुल्य डॉ.आई.एन.ए. सिंह ने किया।

पर ही अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना नियमित विभाग ने सख्त बर्तन अधिमान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर रही तीन बसों को सीज कर दिया गया। अधिमान का नवतुल्य डॉ.आई.एन.ए. सिंह ने किया।

शिक्षा, संस्कार व रोजगार और गुरुखनाथ महापर्व पर हुई चर्चा

शाह टाइम्स संवाददाता
बड़ौदा। हस्तशिल्प क्षेत्र के श्रमकों में अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय सेवा संघन द्वारा आयोजित उपाध्याय समाज के सम्मेलन में शिक्षा, संस्कार, रोजगार और गुरुखनाथ महापर्व पर चर्चा हुई। जनपद बागपत व अन्य जनपदों से आये उपाध्याय उपाध्याय के कर्मचारियों ने समाज की एकता और समाज में संचालित विभिन्न संगठनों के समन्वित पर बल दिया। अन्तिम अतिथियों को पाण्डेय पटका पहनाकर सम्मानित किया गया।

उपाध्याय सेवा संघन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बागपत उपाध्याय ने कहा उपाध्याय समाज के 12 मई 2026 को आने-अपने विचारों में गुरु गोखनाथ महापर्व मनाने की प्रेरणा देता है। सम्मेलन को मुख्य रूप से समाजसेवी आरआरटी उपाध्याय, धर्मवीर उपाध्याय, राजश्री, सामेली जिलाध्यक्ष शिवानी उपाध्याय, रावकुमार पटवर्धन, सनी योगी, मुकुंदा कुमार उपाध्याय ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर ललित, रजनीश उपाध्याय, कमल, विकास, देवेन्द्र, नरेश, सुखवीर सिंह, चरण उपाध्याय, मांगिम उपाध्या आदि रहे।

प्रत्येक वार्ड, ग्राम पंचायत और मोहल्ले के स्तर पर सूक्ष्म योजना की जाए तैयार

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। सोमवार को विभागीय अधिकारियों ने अस्मिता लाल ने जनपद बागपत के 100 वार्डों को पहचानने में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से बागपत कलेक्टर के सहायक में आयोजित विशेष बैठक में संयोजित अधिकारियों को विस्तृत आदेश दिए गए। निर्देश



संघानना है, जिनमें नही कली एवं स्वच्छ परिवहन सुव्यवस्था के रूप में जनपद बागपत के कर दिखाना है। इन मॉडलों के माध्यम से न केवल कचरे का उपयोग प्रबंधन हुआ है, बल्कि स्वच्छ रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर भी सुनिश्चित हुए हैं। कृदा समस्या तब बनता है जब उसका निराकरण सही ढंग से नहीं हो पाता। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत एवं नगर किण्वन इन कुच्छेड मॉडल को अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करें, ताकि कचरे से आग का जोखिम कम हो और स्वच्छता के स्तर में सुधार हो।

गैस सिलेंडर की दिक्कत के चलते कोयले की भट्टी पर बनाए भट्टे

शाह टाइम्स संवाददाता
बड़ौदा। हस्तशिल्प क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में गैस की समस्या बुराकर रहती है। दुकानदार परिवारों को लक्ष्य हो रहे हैं शहरी ग्राम क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की दिक्कत को दायित्व और बढती कीमतों का आरंभ अब तक देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर की दिक्कत के चलते कोयले की भट्टी पर भट्टे बनाए शहर के कारीगर इसी के साथ-साथ स्टूडेंट्स क्लब का भी गैस सिलेंडर की कमी को दूर करने में मदद कर रहे हैं।

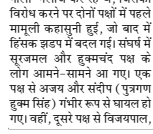
कहना है कि पहले व्यावसायिक गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाते थे, मगर अब तीन-तीन दिन एंजिनी ऊपर जाकर लंबी लाइन में लगकर भी सिलेंडर नहीं आसानी मिल रही है। कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं परंतु तक लाइन में लगने के बाद भी बंधे बंधे इन्हें गैस सिलेंडर मंगाया जाता है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण कोयले की भट्टी पर भट्टे बनाए शहर के कारीगर इसी के साथ-साथ स्टूडेंट्स क्लब का भी गैस सिलेंडर की कमी को दूर करने में मदद कर रहे हैं।

दो पक्षों के बीच लाठी-डंडों से हिंसक झड़प

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। विनोली बाला क्षेत्र के कल्याण गांव में विवादित पक्ष के पक्षों के बीच लाठी-डंडों से हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पंचायत के दोनों पक्षों के गांवों में भी तोड़फोड़ की गई। यह घटना शरव पीकर ग्रामीणों-गंवा घायलों का विरोध करने पर शुरू हुई। रात करीब दस बजे एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर के बाहर शरव पीकर गलती-गलती कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में पहले मामूली कलह शुरू हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। पंचायत में सरसाम और इस्लाम पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। एक पक्ष से अनाथ और विधवा (उपग्राम हनुम सिंह) गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे पक्ष से विधवा, लड़का

दखले हुए मिटाई और समोसे अन्य सामग्री के दम भंगे हुए हो गए हैं। कोयले पर काम करना ऐसी गामी में कारीगर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार मुश्किल सुनते हैं परंतु पक्षों की दिक्कत को दायित्व और बढती कीमतों का आरंभ अब तक देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर की दिक्कत के चलते कोयले की भट्टी पर भट्टे बनाए शहर के कारीगर इसी के साथ-साथ स्टूडेंट्स क्लब का भी गैस सिलेंडर की कमी को दूर करने में मदद कर रहे हैं।

हाईवे पर भूसे से भरें ट्रैक्टर-ट्राली में अचानक लगी भयंकर आग, डेढ़ किलोमीटर तक चलता रहा ट्रैक्टर



शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। दिल्ली-सहारनपूर हाईवे पर देर गांव भूसे से भरें एक ट्रैक्टर-ट्राली में अचानक आग लग गई। कलेक्टर के पास हुई इस घटना से हाइवे पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क के एक तरफ लंबा जाम लगा गया। आग लगते ही मौके पर थुआ और लफ्टे उड़ने लगे, जिससे गुजर रहे गांव वालों में दहशत फैल गई। देर तुरंत हाइवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। जनपदारी के मुताबिक, सौराणा से भूसे लफ्टे आ रहे ट्रैक्टर चालक नाराद को आग लगने का शुरु में पता ही नहीं चलता। सड़क से आ रहे कुछ वाहन चालकों ने उन्हें आवाज देकर भी इशारा करके आग लगने की जानकारी दी। नाराद ने बताया कि आग लगने के बाद भी वह करीब डेढ़ किलोमीटर तक ट्रैक्टर

गेम खेलने से रोकेन पर कठिनाई नगरे सुखाई कपूर की गोलियां

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। मोहाड़ गांव की लाल एक बार फिर खतरनाक साबित होनी दिल्ली परिवार द्वारा गेम खेलने से रोके जाने पर कठिनाई नगरे सुखाई कपूर की गोलियां खा लीं। हालात बिगड़ते पर उदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य रही जा रही है।

खेलने से रोका, जिससे नाराज होकर उठने पर में रखी कपूर की गोलियां खा लीं। पटना के बाद समर की बीबीएन बिगड़ गई। पर, जिनमें से उदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य रही जा रही है।

जिन क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति कमजोर है वहां विशेष ध्यान दिया जाए-डीएम

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। शौकदा क्षेत्र में औद्योगिक इकायों की तिस्टिफिकेशन कर उन्हें प्रगती से जोड़ने के निर्देश दिए गए, जिससे औद्योगिक प्रदूषण को भी वैज्ञानिक निराकरण सुनिश्चित हो और परिवहन प्रदूषण को भी कम किया जा सके। काटा एवं हसनपुर मसूरी में विशेष प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए, साथ ही बोडोंओं को संबोधित सचिवों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित और प्रभावी कार्रवायों सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति कमजोर है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए और नियमित निरीक्षण के माध्यम से सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह

निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में बिना अनुमति खनन या परिवहन बढीर नहीं किया जाएगा। अवैध खनन पर रोक से जहां एक ओर सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं परिवहन कर कार्रवाई संभव हो सकेगी। नर्तियों और आर्थिक संस्थानों की सहायता को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने वैध खनन पट्टियों को भी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अस्मिता लाल स्वयं इस पूरे अभियान की निगरानी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई में किसी प्रकार की हिलाई न बरती जाए और हर स्तर पर पादर्शिता बनाए रखी जाए। इस अवसर पर आम जनता के प्रति जागरूकता के लिए जिलाधिकारी विन राजस्व विनोत कुमार उपाध्याय, जिला अधिकाारी वीरेंद्र प्रताप सिंह, समय परवर्षीण अग्रवाल वरमा श्यामा सिंह, निवेत वरमा शक्ति संयोजित धान प्रभारी उपस्थित रहे।

भाजपा कार्यालय पर मनाया 47वां स्थापना दिवस



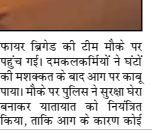
शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। भाजपा कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की स्थापना दिवस को पर्व की तरह मनाते हुए ध्वजारोहण कर पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं के संपर्कों को बढ़ा दिया गया। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के परचम गीत कर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सभ्य सकार की ओर अग्रिम को नमो-गाने तक पहुंचाने और सुरासन का संकल्प लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गौरवशाली दिशाएं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में

हाईवे पर भूसे से भरें ट्रैक्टर-ट्राली में अचानक लगी भयंकर आग, डेढ़ किलोमीटर तक चलता रहा ट्रैक्टर



बहा हादसा न हो। आग बुझने के बाद ही हाइवे पर स्थिति सामान्य हो सकी। आग लगने की वजह से हाइवे के कुछ हिस्से पर रखा जा रहा लगा गया। कई वाहन कुछ देर तक सड़क पर पड़े रहे। पुलिस ने तत्काल ट्रैक्टर डायरेक्ट डेअर और ट्रैक्टर को नियंत्रित कर यातायात व्यवस्था को सुचारु कराया। स्थिति सामान्य होने के बाद स्थानीय लोगों और बाहन चालकों ने राहत की सांस ली। ट्रैक्टर चालक नाराद ने बताया कि इस आगजनी में उनके ट्रैक्टर-ट्राली और भूसे को लाशों रूप का नुकसान हुआ है। फिलहाल आम लोगों के कार्यों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि आग किसी तकनीकी खराबी या विद्युत की वजह से लगी हो सकती है। पुलिस और संबंधित टीमों मामले की जांच में जुटी है।

जंगल में हाईस्टेशन विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरा, किसानों की बाल-बाल बची जान



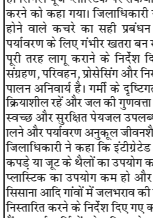
बागपत। सोमवार को जिवाना गुलियाण व मलामताजग गांव के जंगल में हाईस्टेशन विद्युत तार का तार टूट गया। इसमें किसान हरद सोलंकी को दस बीघा गेहूँ की फसल जलने से बाल-बाल बची गई। घटना के बाद पुष्पासा किसानों ने प्रदर्शन कर उन्हें विद्युत लाइन चलाने को मजबूरी की। किसान हरद सोलंकी ने बताया कि उनके क्षेत्र के पास ही गुजर रही हाईस्टेशन विद्युत लाइन का तार हालत में है। सोमवार को इसी तार का एक तार टूटकर गिरा, जिससे अंततः कर बीघे बगीचे की फसल में आग लग गई। आग लगने से उनकी गेहूँ की फसल को और बर्ह रही थी। हरद सोलंकी और शिवदत्त ने तुरंत बिजलीघर पर कान कर विद्युत आपूर्ति बंद कराया। इसके बाद किसी तरह आग का कब्जा पक गया।

एक नजर

कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। डीएम और अधिकारियों ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी का निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, सभी कार्यों को उचित सुनिश्चित हो और पूरी प्रक्रिया को नियमित निगरानी की जाए। विभाग स्थलों की मीटिंग के निर्देश दिए गए, ताकि वहां से निकलने वाले कूड़े-कचरे का प्रभावी और वैज्ञानिक निराकरण किया जा सके। साथ ही स्थिति पूर्ण प्वास्टिक पर रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े आयोजनों में उत्पन्न होने वाले कचरे का सही प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, अतः यह प्वास्टिक के लिए गंभीर ध्यान देना चाहिए। मौलिक सेट मैनेजमेंट को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रोसेसिंग और निराकरण-इन सभी चरणों में मानकों का पालन अनिवार्य है। कमी के परिपन्ना सभी क्षेत्रों में स्थापित खाद कुरल क्रियाशील रहे और जल को गुणवत्ता की निगरानी होनी चाहिए। ताकि लोगों की स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध हो सके। बागपतकालीन विभाग, लाने और परिवहन अकुल प्रवर्धनीय को बढ़ाव देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि इंटीग्रेटेड मॉडल पर कार्य करवा हूए लोगों को कपड़े या पट्टे के अलावा अन्य सामग्री के साथ प्रवर्धनीय का बंधन है। किसान प्वास्टिक का उपयोग को हो और प्वास्टिक संरक्षण को बढ़ावा मिले। किसानों और गांवों में जनप्रतिक्रिया के माध्यम से स्थानीयता को आधुनिक निराकरण के निर्देश दिए गए क्योंकि वे क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं। सफाई कर्मियों को साफ और संयोजित प्रक्रिया कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमी को स्पष्ट लक्ष्य दिया जाएगा और उनका कार्य का निगरानी मूल्यांकन किया जाएगा। साइको जालों के आधार पर कार्य किया जाए और सभी वितरित व्यवस्थित रूप से रखे जाएं, ताकि प्रत्येक गतिविधि का रिजल्ट उपलब्ध रहे और आवश्यकता पड़ने पर उसका विवरण दिया जा सके।

जंगल में हाईस्टेशन विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरा, किसानों की बाल-बाल बची जान



बागपत। सोमवार को जिवाना गुलियाण व मलामताजग गांव के जंगल में हाईस्टेशन विद्युत तार का तार टूट गया। इसमें किसान हरद सोलंकी को दस बीघा गेहूँ की फसल जलने से बाल-बाल बची गई। घटना के बाद पुष्पासा किसानों ने प्रदर्शन कर उन्हें विद्युत लाइन चलाने को मजबूरी की। किसान हरद सोलंकी ने बताया कि उनके क्षेत्र के पास ही गुजर रही हाईस्टेशन विद्युत लाइन का तार हालत में है। सोमवार को इसी तार का एक तार टूटकर गिरा, जिससे अंततः कर बीघे बगीचे की फसल में आग लग गई। आग लगने से उनकी गेहूँ की फसल को और बर्ह रही थी। हरद सोलंकी और शिवदत्त ने तुरंत बिजलीघर पर कान कर विद्युत आपूर्ति बंद कराया। इसके बाद किसी तरह आग का कब्जा पक गया।

एक नजर

कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। डीएम और अधिकारियों ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी का निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, सभी कार्यों को उचित सुनिश्चित हो और पूरी प्रक्रिया को नियमित निगरानी की जाए। विभाग स्थलों की मीटिंग के निर्देश दिए गए, ताकि वहां से निकलने वाले कूड़े-कचरे का प्रभावी और वैज्ञानिक निराकरण किया जा सके। साथ ही स्थिति पूर्ण प्वास्टिक पर रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े आयोजनों में उत्पन्न होने वाले कचरे का सही प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, अतः यह प्वास्टिक के लिए गंभीर ध्यान देना चाहिए। मौलिक सेट मैनेजमेंट को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रोसेसिंग और निराकरण-इन सभी चरणों में मानकों का पालन अनिवार्य है। कमी के परिपन्ना सभी क्षेत्रों में स्थापित खाद कुरल क्रियाशील रहे और जल को गुणवत्ता की निगरानी होनी चाहिए। ताकि लोगों की स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध हो सके। बागपतकालीन विभाग, लाने और परिवहन अकुल प्रवर्धनीय को बढ़ाव देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि इंटीग्रेटेड मॉडल पर कार्य करवा हूए लोगों को कपड़े या पट्टे के अलावा अन्य सामग्री के साथ प्रवर्धनीय का बंधन है। किसान प्वास्टिक का उपयोग को हो और प्वास्टिक संरक्षण को बढ़ावा मिले। किसानों और गांवों में जनप्रतिक्रिया के माध्यम से स्थानीयता को आधुनिक निराकरण के निर्देश दिए गए क्योंकि वे क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं। सफाई कर्मियों को साफ और संयोजित प्रक्रिया कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमी को स्पष्ट लक्ष्य दिया जाएगा और उनका कार्य का निगरानी मूल्यांकन किया जाएगा। साइको जालों के आधार पर कार्य किया जाए और सभी वितरित व्यवस्थित रूप से रखे जाएं, ताकि प्रत्येक गतिविधि का रिजल्ट उपलब्ध रहे और आवश्यकता पड़ने पर उसका विवरण दिया जा सके।

एक नजर

कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। डीएम और अधिकारियों ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी का निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, सभी कार्यों को उचित सुनिश्चित हो और पूरी प्रक्रिया को नियमित निगरानी की जाए। विभाग स्थलों की मीटिंग के निर्देश दिए गए, ताकि वहां से निकलने वाले कूड़े-कचरे का प्रभावी और वैज्ञानिक निराकरण किया जा सके। साथ ही स्थिति पूर्ण प्वास्टिक पर रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े आयोजनों में उत्पन्न होने वाले कचरे का सही प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, अतः यह प्वास्टिक के लिए गंभीर ध्यान देना चाहिए। मौलिक सेट मैनेजमेंट को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रोसेसिंग और निराकरण-इन सभी चरणों में मानकों का पालन अनिवार्य है। कमी के परिपन्ना सभी क्षेत्रों में स्थापित खाद कुरल क्रियाशील रहे और जल को गुणवत्ता की निगरानी होनी चाहिए। ताकि लोगों की स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध हो सके। बागपतकालीन विभाग, लाने और परिवहन अकुल प्रवर्धनीय को बढ़ाव देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि इंटीग्रेटेड मॉडल पर कार्य करवा हूए लोगों को कपड़े या पट्टे के अलावा अन्य सामग्री के साथ प्रवर्धनीय का बंधन है। किसान प्वास्टिक का उपयोग को हो और प्वास्टिक संरक्षण को बढ़ावा मिले। किसानों और गांवों में जनप्रतिक्रिया के माध्यम से स्थानीयता को आधुनिक निराकरण के निर्देश दिए गए क्योंकि वे क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं। सफाई कर्मियों को साफ और संयोजित प्रक्रिया कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमी को स्पष्ट लक्ष्य दिया जाएगा और उनका कार्य का निगरानी मूल्यांकन किया जाएगा। साइको जालों के आधार पर कार्य किया जाए और सभी वितरित व्यवस्थित रूप से रखे जाएं, ताकि प्रत्येक गतिविधि का रिजल्ट उपलब्ध रहे और आवश्यकता पड़ने पर उसका विवरण दिया जा सके।

एक नजर

कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी

शाह टाइम्स संवाददाता
बागपत। डीएम और अधिकारियों ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, पूरी प्रक्रिया की नियमित की जाए निगरानी का निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कलेक्शन वाहन समय पर पहुंचे, सभी कार्यों को उचित सुनिश्चित हो और पूरी प्रक्रिया को नियमित निगरानी की जाए। विभाग स्थलों की मीटिंग के निर्देश दिए गए, ताकि वहां से निकलने वाले कूड़े-कचरे का प्रभावी और वैज्ञानिक निराकरण किया जा सके। साथ ही स्थिति पूर्ण प्वास्टिक पर रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े आयोजनों में उत्पन्न होने वाले कचरे का सही प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, अतः यह प्वास्टिक के लिए गंभीर ध्यान देना चाहिए। मौलिक सेट मैनेजमेंट को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रोसेसिंग और निराकरण-इन सभी चरणों में मानकों का पालन अनिवार्य है। कमी के परिपन्ना सभी क्षेत्रों में स्थापित खाद कुरल क्रियाशील रहे और जल को गुणवत्ता की निगरानी होनी चाहिए। ताकि लोगों की स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध हो सके। बागपतकालीन विभाग, लाने और परिवहन अकुल प्रवर्धनीय को बढ़ाव देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि इंटीग्रेटेड मॉडल पर कार्य करवा हूए लोगों को कपड़े या पट्टे के अलावा अन्य सामग्री के साथ प्रवर्धनीय का बंधन है। किसान प्वास्टिक का उपयोग को हो और प्वास्टिक संरक्षण को बढ़ावा मिले। किसानों और गांवों में जनप्रतिक्रिया के माध्यम से स्थानीयता को आधुनिक निराकरण के निर्देश दिए गए क्योंकि वे क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं। सफाई कर्मियों को साफ और संयोजित प्रक्रिया कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमी को स्पष्ट लक्ष्य दिया जाएगा और उनका कार्य का निगरानी मूल्यांकन किया जाएगा। साइको जालों के आधार पर कार्य किया जाए और सभी वितरित व्यवस्थित रूप से रखे जाएं, ताकि प्रत्येक गतिविधि का रिजल्ट उपलब्ध रहे और आवश्यकता पड़ने पर उसका विवरण दिया जा सके।

NOTICE
In The School Records Of My Son, Awash Siddhi (Class 9-D), My Name is Listed As "Chand." Which is Incorrect. My Correct Name is "Anand Siddhi." Please Ensure That My Name is Recorded As "Anand Siddhi" in My Son's School Records. Chand Siddhi, S/O. Harnid, Rio Muglaipura, Tehsil & Distt. Baghatpur-250611 (UP).

बातचीत, जंग साथ-साथ

पश्चिमी एशिया में जारी ईरान-अमेरिका/इस्राइल युद्ध धमके का नाम नहीं ले रहा है। 137 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस युद्ध का कहीं से भी अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है जिसमें पद के पीछे इस संघर्ष को रोकने के लिए कोशिशों की बात सामने आई है। पहली बार ईरान ने माना है कि उसे मध्यस्थता के जरिये से अमेरिका की तरफ से युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव मिला है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने ऐसा कहते हुए यह भी जोड़ा कि जब तक अमेरिका व इस्राइल हमले तेज करते रहेंगे, वह सीधे वार्ता में शामिल नहीं होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव अत्यधिक मांगों वाला है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि ईरान ने भी अपनी मांगों का एक अलग सेंट तैयार कर लिया है और उसे औपचारिक रूप दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने तेहरान में कहा कि इस्राइल अमेरिका की कोई रेडलाइन नहीं है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह नहीं करते। उन्होंने अमेरिका के कथित 15 सूत्रीय प्रस्ताव को तर्कहीन करार दिया। उनका कहना था कि किसी भी समझौते को तभी स्वीकार किया जाएगा जब ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा। उन्होंने अस्थायी युद्ध के बदले होमरुज को खोलने के लिए मना कर दिया। एक अन्य सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है लेकिन दबाव में फंसला नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अभी भी मध्यस्थता की भूमिका में बना हुआ है। ईरान ने साफ किया कि युद्ध विराम के बलदे होमरुज नहीं खोलेगा। ईरान का अभी भी यह मानना है कि अमेरिका स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है और ईरान के लिए अस्थायी युद्ध का कोई मतलब नहीं है। बात घूम-फिरकर फिर वहीं आ जाती है, जब तक दोनों पक्षों के बीच में ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे, जिससे जो अविश्वास की खाई जो बहुत गहरी हो चुकी है, उसको पाटा नहीं जाएगा तब तक किसी शांति समझौते पर पहुंचना आसान नहीं होगा। इस समय की यही दिशा दे रहा है। शांति के प्रयास भी हो रहे हैं और युद्ध की तीव्रता में किसी तरह की कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इन हमलों का दायरा इतना बढ़ चुका है कि अब इसकी जद में पुल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हेल्थ सेंटर भी आने लगे हैं। सवाल है ऐसे में संघर्ष विराम पर कैसे अमल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सुपर पावर के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। वह अभी भी ईरान को धमकी भरी भाषा में चेता रहे हैं। उन्होंने अपने दस दिनों के अल्टीमेटम में अब 48 घंटों का अतिरिक्त इजाफा कर दिया है, लेकिन वह भी धमकी के साथ कि होमरुज को खोलो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा।

नतीजा शहर छोड़ो, गांव भागो

प्रधानमंत्री मोदी के पास रसोई गैस (एलपीजी) संकट से निपटने की कोई नीति नहीं है और इस समय भी वही अवस्था देखने को मिल रही है जो देश के लोगों ने कोविड के समय देखी थी, मोदी जी ने कहा था कि एलपीजी संकट को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वही किया, बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य, घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर, हर रोज 500-800 की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है, रात को घर लौटते मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं, नतीजा शहर छोड़ो, गांव भागो, जो मजदूर कपड़ा मिल और फैक्टरियों की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं। कपड़ा क्षेत्र पहले से ही गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में है।

—राहुल गांधी, नेता विपक्ष, लोकसभा

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 16 अप्रैल का दिन एक युगांतरकारी मोड़ साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को धरातल पर उतारने के लिए एक साहसिक और दूरगामी योजना तैयार की है। इस योजना के केंद्र में केवल महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि लोकसभा की संरचना में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार भी शामिल है। मसलन नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बड़े संशोधनों के साथ ही लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य न केवल विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, बल्कि दशकों से लंबित परिसीमन की प्रक्रिया को एक नई दिशा देना भी है। सरकार द्वारा इस तैयारी के लिए खींचे गए खाकें को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वह महिलाओं को संसद में भेजने के अपने वादे को 2029 के आम चुनाव तक हर हाल में पूरा करना चाहती है। देश को उम्मीद है कि लोकसभा की नई संरचना न केवल भारत की बढ़ती आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी, बल्कि नारी शक्ति को राष्ट्र के नीति-निर्माण में बराबर का हिस्सेदार बनाएगी।

संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में उस समय चौकाने वाला निर्णय लिया, जिसमें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने वाले बजट सत्र को समाप्त करने के बजाय, 16 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। यानी संसद का बजट सत्र का यह विशेष हिस्सा अब 16 से 18 अप्रैल तक फिर से चलेगा। केंद्र सरकार का मकसद महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को समय से पहले जमीन पर उतारना है। सरकार का पूरा फोकस अब उस कानूनी अडचन को खत्म करना है, जो महिला आरक्षण और जनगणना तथा परिसीमन के बीच फंसी हुई है। दरअसल 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक, आरक्षण अगली जनगणना के बाद ही लागू हो सकता था, जिसमें वर्षों का समय लगना स्वाभाविक था। अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही लंबित परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को उनके हक के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इसलिए जनगणना और परिसीमन की तकनीकी अडचनों को दूर करने के लिए पथ संभलाने का पथ साबित होगा।

इस सत्र के विस्तार का सबसे बड़ा आकर्षण लोकसभा सीटों का पुनर्गठन हो सकता है। चर्चा है

राजनीति का नया भूगोल लोकसभा विस्तार व नारी शक्ति का नया उदय



कि सरकार सदन में सीटों की संख्या 543 में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे लोकसभा की 816 सीटें होने पर 33 प्रतिशत यानी एक-तिहाई आरक्षण के फार्मूले के तहत लोकसभा में लगभग 273 सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मसलन इन 273 सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उनके आरक्षित कोटे के भीतर सीटें तय होंगी।

संसद में यदि यह संशोधन पास होता है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही देश की संसद का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि इसके लिए बजट सत्र की आगामी तीन दिन की बैठकों में सरकार जहां एक संविधान संशोधन विधेयक के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव करेगी। वहीं दूसरा सामान्य विधेयक परिसीमन अधिनियम में संशोधन लाएगी।

इन दोनों प्रस्तावित कानून 31 मार्च 2029 से लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो आगामी लोकसभा चुनावों और ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। यही फार्मूला राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू किया जाएगा, ताकि

पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक समान ढांचा तैयार हो सके। माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल दक्षिणसीटों की संख्या बढ़ने से बड़े राज्यों, विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी उछाल आएगा। नए परिसीमन के जरिए राज्यों में फिलहाल संसदीय सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी होगी और उत्तर प्रदेश में यह संख्या सबसे ज्यादा होकर तीन अंक में पहुंच जाएगी।

लोकसभा का ऐतिहासिक विस्तार

वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जो 1971 की जनगणना के आधार पर टिकी हुई है। सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार यदि सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी। इस विस्तार का आधार 2011 की जनगणना को बनाया जाएगा यानी अब 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही सीटों का पुनर्गठन (परिसीमन) किया जाएगा। यह कदम इसलि महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जनगणना में होने वाली देरी के कारण आरक्षण के क्रियान्वयन में बाधा आ रही थी। यदि ए दोनों विधेयक संसद में पारित होते हैं, तो महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी। जिनमें महिलाओं के लिए 24 सीटें

ओ.पी. पाल



आरक्षित होगी। बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है, जहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती हैं। मध्यप्रदेश में 29 से 44 सीटों में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 39 से 59 प्रस्तावित सीटों में 20 और दिल्ली प्रस्तावित 11 में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है, जहां फिलहाल 14 सीटें हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों की सीटें भी नए परिसीमन में बढ़ेंगी।

कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां

सरकार को हालांकि इस ऐतिहासिक बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए ए दो मोर्चों पर काम करना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन के लिए सरकार को संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता है।

यानी इन दोनों विधेयकों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। यही कारण है कि इसके लिए गुहमंत्रि अमित शाह सपा, राजद, बीजद, वार्डएसआर कांग्रेस, एनसीपी (एनपी) और एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दलों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल लगातार मांग कर रहे हैं कि महिला कोटे के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान शामिल नहीं है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सरकार इसी फार्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे।

इतिहास बदलने और भविष्य गढ़ने वाले कदम

वारिसों और महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार अब सुनिश्चित और संरक्षित हैं। यह प्रावधान माननीय और दुरुपयोग को रोकता है और दानकर्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ करता है। संघर्षों की संख्या बढ़ेगी और उनका उपयोग स्पष्ट, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित होगा। यह कदम वक्फ संघर्षों के दुष्प्रयोग को समाप्त करने में मदद करेगा और भरोसा, स्थिरता और सुरक्षा की नई भावना पैदा करेगा। विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार न्याय की गति को तेज करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा।

प्रो. आर.के. जैन



जब कोई कानून केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहकर समाज की रोजमर्रा की ज़िंदगी में वास्तविक बदलाव लाता है, तभी उसका ऐतिहासिक महत्व अमिट हो जाता है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के साथ वक्फ संशोधन कानून ने भारतीय वक्फ संघर्षों के प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक और क्रांतिकारी कदम है। पुराने तंत्र में भ्रष्टाचार, मनमानी और अतिक्रमण ने संघर्षों में मिलने वाले वास्तविक लाभ को लगातार रोके रखा था। अब वक्फ बोर्डों का अधिकार, निकाय तर्कनीक, उत्तरदाई प्रबंधन और समावेशी, पिटकोण के साथ काम करेगा। इसका असर केवल संघर्षों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसे मूलभूत जरूरतों में सीधे दिखाई देगा। यह परिवर्तन करोड़ों मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षा, विश्वास और समृद्धि का एक नया संदेश लेकर

आया है। वक्फ संघर्षों के प्रबंधन में पहले अनियमित, ताओं और विवादों की लंबी श्रंखला रही, जिसने उनकी वास्तविक उपयोगिता और विकास को लगातार बाधित किया। मनमाने दावे, लंबित मुकदमें और अतिक्रमण ने कई संघर्षों को विवादास्पद और अनुपयोगी बना दिया था। अब डिजिटल पोर्टल और ऑटोमेशन के माध्यम से प्रत्येक संघर्ष का पूरा जीवनचक्र ट्रैक किया जाएगा। पंजीकरण, लेखा-जोखा, ऑडिट और मुकदमेबाजी सभी ऑनलाइन और पारदर्शी होंगे। छह माह के भीतर सभी संघर्षों पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगे, जिससे कोई भी संघर्ष छिपी नहीं रहेगा। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करेगी और वक्फ बोर्डों को एक वैज्ञानिक, उत्तरदाई और आधुनिक संस्था में परिवर्तित कर देगी। परिणामस्वरूप, संघर्षों का उपयोग अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और न्यायसंगत ढंग से सुनिश्चित होगा।

जिला कलेक्टर को संपत्ति सर्वेक्षण और विवाद समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा। अब निर्णय केवल सरकारी रिपोर्टों और निष्पक्ष जांच पर आधारित होंगे। अतिक्रमण स्वतः रोक जाएगा और संपत्तियां उनके वास्तविक लाभार्थियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचेंगी। कलेक्टर का समयबद्ध और तथ्यपरक दृष्टिकोण हर निर्णय को मजबूत और भरोसेमंद बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप, वक्फ संघर्षों शीघ्र और प्रभावी कल्याण कार्यों में लगेगीं। विवाद कम होंगे, संघर्षों का विकास तेजी से होगा और गरीब, विधवा एवं वंचित वर्गों तक लाभ

वक्फ के लिए नए नियम

सुनिश्चित रूप से पहुंचेंगे। यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। समावेशिता और संतुलित नेतृत्व अब वक्फ बोर्ड की नई पहचान बन चुका है। बोर्डों में अब कम से कम दो मुस्लिम महिलाएं और गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे।

विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया व्यापक दृष्टिकोण वाली, संतुलित और संवेदनशील बनेगी। महिलाओं की भागीदारी प्रबंधन में संवेदनशीलता और सुझाव लाएगी, जबकि गैर-मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक निगरानी और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। यह संरचना वक्फ को केवल धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त प्रतीक बनाएगी। प्रत्येक वर्ग का सक्रिय योगदान विकास की दिशा में सुनिश्चित होगा और कल्याण कार्यों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। संपत्ति दान और वक्फ गठन के नए नियम इसे सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाते हैं। अब केवल पांच वर्ष से इस्लाम का पालन करने वाला वास्तविक और सच्चा मालिक ही संपत्ति वक्फ कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर जैसे पुरानी और असुरक्षित प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

स्वास्थ्य विषमता के विरुद्ध सबसे बड़ा अस्त्र है वैज्ञानिक चेतना

हर वर्ष 7 अप्रैल को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' मनाया जाता है, जो मानव सभ्यता को आईना दिखाने वाला एक वैश्विक आत्ममंथन है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों, दवाइयों और डॉक्टरों तक सीमित अवधारणा नहीं बल्कि एक समग्र स्थिति है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन निहित है। इस वर्ष यह दिवस स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहें थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो अत्यंत प्रासंगिक, विचारोत्तेजक और दूरदर्शी संदेश लेकर आ रहा है। विश्व की आधी से अधिक आबादी आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है और करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपनी आय का बड़ा हिस्सा केवल इलाज पर खर्च करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाती है बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।

कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने तो पूरी दुनिया के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली कितनी भी विकसित क्यों न हो, यदि उसमें समावेशिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है तो वह संकट के समय लड़खड़ा सकती है। विकसित देशों में भी स्वास्थ्य संसाधनों की कमी ने यह सिद्ध किया कि केवल आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं बल्कि वैज्ञानिक तैयारी, स्वास्थ्य अवसरों और जनविश्वास का समन्वय ही वास्तविक स्वास्थ्य प्रदान करता है। महामारी के दौरान वैक्सीन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर फैली अफवाहों और गलत

कुलमिलाकर, विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें एक सामूहिक संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत चिंता नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें।

सूचनाओं ने यह भी दिखाया कि विज्ञान के प्रति अविश्वास स्वयं एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। इसलिए इस वर्ष की थीम हमें यह संदेश देती है कि विज्ञान के साथ खड़ा होना केवल एक कल्प नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या वाले देश के रूप में भारत के सामने स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां बहुआयामी हैं। एक ओर संक्रामक रोगों का खतरा अभी भी बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर गैर-संचारी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां आज देश में मृत्यु के प्रमुख कारण बन चुकी हैं। बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, मानसिक तनाव और शारीरिक निष्क्रियता ने इन रोगों को और अधिक बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आने वाले वर्षों में इन बीमारियों का बोझ और भी अधिक बढ़ने वाला है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसके साथ ही भारत में जनसंख्या संरचना में हो रहे परिवर्तन भी एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के साथ अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी

बीमारियों का प्रसार बढ़ने की आशंका है। यह न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचना के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इन परिस्थितियों में केवल पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं होंगी बल्कि एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना आवश्यक होगा, जिसमें रोकथाम, जागरूकता और दीर्घकालिक देखभाल को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य अवसरों की बात करे तो भारत में अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच गहरी खाई मौजूद है। जहां शहरों में आधुनिक अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी देखी जाती है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी इस समस्या को और जटिल बनाती है। ऐसे में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमैडिसिन और ई-हेल्थ प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर रहे हैं। यह तकनीकी दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन इनका प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की पहुंच को भी समान रूप से बढ़ाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में एक स्वास्थ्य की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। इसलिए स्वास्थ्य नीतियों को केवल चिकित्सा तक सीमित न रखकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से भी जोड़ना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा-आधारित नीतियों के माध्यम से ही इन जटिल चुनौतियों का समाधान संभव है। आज के समय

में एक और बड़ी चुनौती है ग्रामिक सूचनाओं का प्रसार। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार के साथ गलत जानकारी तेजी से फैलती है, जो लोगों के स्वास्थ्य निर्णयों को प्रभावित करती है। वैकसीन विरोधी अभियान, अप्रमाणित उपचार पद्धतियों का प्रचार और छद्म विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक नया खतरा उत्पन्न कर दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक तथ्यों को सरल और प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जाए और लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित की जाए। सरकारों की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, अनुसंधान को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिकरण ऐसे कदम हैं, जो इस दिशा में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका क्रियान्वयन कितनी पारदर्शिता और प्रभावी शीलता के साथ किया जाता है। विज्ञान और तकनीक की भूमिका को भी इस संदर्भ में अनादेखा नहीं किया जा सकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। रोगों की प्रारंभिक पहचान, व्यक्तिगत उपचार और दवाओं के विकास में यह तकनीकी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हालांकि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन तकनीकों का लाभ

योगेश कुमार गोयल



समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहे जाए। यह समझना भी आवश्यक है कि स्वास्थ्य केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह एक सामूहिक दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा और स्वस्थ जीवनशैली अपनानी होगी। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान और स्वच्छता जैसे छोटे-छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को भी बढ़ावा देना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। विश्व स्वास्थ्य दिवस का संदेश यही है कि यदि हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कल्पना करनी है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा। वैज्ञानिक सोच, वैश्विक सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का संगम ही वह मार्ग है, जो हमें स्वास्थ्य की समानता और सार्वभौमिकता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। यह केवल एक दिवस का संदेश नहीं बल्कि एक सतत संकल्प है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



शिमला। लाहौल-स्पीति जिले के रोहतंग स्थित अटल सुरंग के उतरी प्रवेश द्वार पर बर्फ के बीच साहसिक गतिविधियों में भाग लेते पर्यटक।

जापोरोजे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थिति लगातार तनावपूर्ण: चेर्न्युक

मास्को। जापोरोजे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निद्राशक यूरी चेर्न्युक ने कहा है कि संयंत्र की सुविधाओं और शहर पर युद्ध के प्रभाव के कारण वहाँ की स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। संयंत्र की प्रवक्ता एवगेनिया याशिना ने शुक्रवार को बताया था कि पिछले दो हफ्तों में जापोरोजे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और एनरगोदर के पास के क्षेत्र में यूक्रेन के सशस्त्र बलों के हमलों की तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है। रोसाटोम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी लिखाचेव ने रविवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में संयंत्र क्षेत्र पर कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन स्टेशन के अनुपंगी शहर एनरगोदर पर हमले हुए हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट की है आशंका: मेलोनी

रोम। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्वीकार किया है कि पश्चिम एशिया में स्थिति और बिगड़ती है तो देश को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 'कोरिरे डेला सेरा' अखबार ने इटली के चार हवाई अड्डों-मिलान, वेनिस, ट्रेविसो और बोल्गोना में जेट ईंधन पर लागू किए गए पहले प्रतिबंध को जानकारी दी। सुमेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि जब खाड़ी देशों में अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका सीधा असर ऊर्जा की लागत, व्यवसायों, नौकरियों और अंततः परिवारों की क़य शक्ति पर पड़ता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में फारस की खाड़ी के देश प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर वहाँ उत्पादन कम या बंद होता है, तो ऊर्जा की कीमतें हर किसी के लिए बढ़ जाएगी।

अमेरिका ने अपने ही विमानों पर बमबारी की: IRGC

ट्रम्प की बेइज्जती से बचने और अपनी सेना की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा: ईरानी वायु रक्षा कमान

तेहरान/नई दिल्ली। ईरान के वायु रक्षा कमान ने कहा है कि अमेरिका की सेना ने बचाव अभियान के दौरान अपने ही विमानों पर बमबारी कर दी। ईरान के एकीकृत वायु रक्षा कमान 'खातम अल-अबिया मुख्यालय' के प्रवक्ता ने कहा कि जब ईरान के लड़ाकू विमानों ने घेराबंदी पूरी कर ली, तो ट्रम्प की बेइज्जती से बचने और अपनी सेना की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने ही गिराए गए विमानों, साजो-सामान, कमांडरों और सैनिकों पर भारी बमबारी करने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई विमानों को निशाना बनाया गया और उन्हें इस्फ़ाहन के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें दो सी-130 सैन्य परिवहन विमान और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने एक बयान में अमेरिका के इस अभियान को 'बिफल' बताया गया और कहा गया कि इसके परिणाम को 'सिर्फ' बयानबाजी, मीडिया युद्ध या मनोवैज्ञानिक अभियानों से ठीक नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने तेहरान के 'शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' को निशाना बनाकर किए गए कथित 'बंकर-बस्टर' बम हमले को निंदा



शरीफ विश्वविद्यालय पर हमला ट्रम्प की अज्ञानता का प्रतीक: मोहम्मद रजा आरिफ बंकर-बस्टर बम हमले की निंदा की

करते हुए इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 'बर्बता' करार दिया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त आरिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि शरीफ विश्वविद्यालय पर बंकर-बस्टर बम हमला ट्रम्प के पागलपन और अज्ञानता का प्रतीक है। ईरानी उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह (ट्रम्प) यह समझने में विफल रहे हैं कि ईरान का ज्ञान केंद्रों में नहीं दबा है जिसे बमों से नष्ट किया जा

जापान ईरान के साथ सीधे संपर्क का कर रहा है उपयोग: ताकाइची

टोक्यो। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान होमरुंज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान के साथ सीधे संचार माध्यमों का उपयोग कर रहा है। सुताकाइची ने संसद में प्रश्नों के उत्तर में कहा कि हमने आज तक विभिन्न स्तरों पर ईरान के साथ धनित संचार बनाए रखा है। फारस की खाड़ी में जापान से जुड़े जहाजों सहित कई जहाजों के फंसने होने पर चिंता व्यक्त करते हुए, हम मांग करते हैं कि ईरानी पक्ष होमरुंज जलडमरूमध्य में सभी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इस के साथ इस सीधे माध्यम का उपयोग करते हुए, हम होमरुंज जलडमरूमध्य में नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों की तलाश जारी रखेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि होमरुंज जलडमरूमध्य में जापानी जहाजों सहित सभी जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में हमले शुरू किए थे। ईरान, इजरायली क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है।

युद्ध कई साल चला, तो भी नहीं होगी मिसाइलों की कमी: ईरान

सैन्य कार्रवाइयों के दौरान पूरी दुनिया के सामने कई क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया

तेहरान/काहिरा। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजरायल के साथ सैन्य संघर्ष कई सालों तक चलता है, तब भी उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं होगी। यह बात ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति पर संसदीय आयोग के सदस्य अलाएदीन बोरूजेदी ने रविवार को कही। ईरानी संसद की एजेंसी 'खाने-ए-मल्लत' ने बोरूजेदी के हवाले से कहा कि अगर यह युद्ध महीनों या सालों तक भी चलता है, तब भी ईरान को मिसाइल और रणनीतिक भंडारों के मामले में कोई समस्या नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ सैन्य कार्रवाइयों के दौरान पूरी दुनिया के सामने कई क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित होता है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें तेहरान भी शामिल था। इससे काफी नुकसान हुआ और आम नागरिकों



अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें तेहरान भी शामिल था

ईरान के बहरेस्तान में अमेरिका और इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत

तेहरान। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के बहरेस्तान में किए गए हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और इजरायली सेना ने बहरेस्तान क्षेत्र के कुलेह मीर शहर में दो रिहायशी इमारतों पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि यह क्षेत्र तेहरान प्रांत का एक घनी आबादी वाला इलाका है। बहरेस्तान के गवर्नर ने बताया कि मलबे को हटाने और मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। की जान भी गई। ईरान ने इसके जवाब में इजरायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वहीं मिस्र में ईरानी के राजनयिक मिशन के प्रमुख मोजतबा फेरदोसीपुर ने कहा है कि ईरान के पास इस बार में कोई जानकारी नहीं है कि खाड़ी के देश इस्लामिक गणराज्य के क्षेत्र पर हुए हमलों में शामिल हैं। फेरदोसीपुर से जब पूछा गया कि क्या खाड़ी के देश ईरानी क्षेत्र पर हमलों में हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में

मध्यस्थता कर रहे 45-दिनों के संभावित संघर्ष-विराम की शर्तों पर चर्चा

मास्को। अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थ संघर्ष को सुलझाने के लिए बनाई गई दो-चरण वाली योजना के पहले चरण के तौर पर 45 दिनों के संभावित युद्धविराम की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। एक्सप्रेस एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रम्प प्रशासन ने हाल के दिनों में ईरान के सामने कई प्रस्ताव रखे थे, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने अभी तक उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटों के भीतर दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते की संभावना कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इससे पहले सोशल मीडिया पर ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और पुलों को मंगलवार को नष्ट करने की धमकी दी है और होमरुंज जलडमरूमध्य को खोलने की मांग की है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक दो-चरण वाले समझौते पर फिलहाल चर्चा चल रही है। पहले चरण में 45 दिनों का युद्धविराम शामिल है, जिसके दौरान आंतिम शांति की शर्तों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि यदि पक्षों को बातचीत के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो इस युद्धविराम को बढ़ाया भी जा सकता है।

ईरान पर अपमानजनक पोस्ट कर फंसे ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ 25वां संशोधन लागू करने की मांग हो रही है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईस्टर की सुबह ईरान को टारगेट करते हुए अपशब्दों से भरा एक पोस्ट टूथ सोशल पर साझा किया था। इसके बाद अमेरिकी सांसदों ने उनके खिलाफ 25वां संशोधन लागू करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ट्रम्प शायद मानसिक तौर पर ठीक नहीं हैं। कनेक्टिकट से डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर मैं ट्रम्प को कैबिनेट में होता, तो मैं ईस्टर पर सांविधानिक वकालतों को 25वां संशोधन के बारे में बताता। बता दें, अमेरिका की 25वां संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के ज्यादातर लोग अपनी ड्यूटी न कर पाने की वजह से राष्ट्रपति को बदलने का विकल्प चुन सकते हैं और फिर उपराष्ट्रपति प्रिंसिपल को भूमिका निभाते हैं। डेमोक्रेटिक सांसद यासमीन अंसारी ने भी पोस्ट किया कि 25वां संशोधन किसी वजह से है। पूर्व होस्ट मेहदी हसन ने लिखा कि राष्ट्रपति का ईस्टर में सेज, जिसके लिए वीपी और कैबिनेट के रूप में जाना जाएगा, जो अपनी तरह का अनोखा होगा।

राजनाथ ने देश के चारों कोनों में सेना के रिसर्च और रेफरल अस्पताल बनाने का सुझाव दिया

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी मेडिकल कोर के 262 वें स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत सोमवार को यहां सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल) में नेत्र विज्ञान, कैंसर चिकित्सा तथा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेंटर्स की आधारशिला रखी तथा दिल्ली छावनी स्थित बेस अस्पताल में नए बुनियादी ढांचे का शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर नवाचार, क्षमता निर्माण और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य नर्सिंग सेवा की नर्सों के योगदान की सराहना की

सोमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब सैनिकों को श्रेष्ठ चिकित्सा सहायता का विचार होता है, तो वे बिना भय के अपने मिशन पूरे करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक मानकों से नहीं आंकी जा सकती, बल्कि जनस्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। चिकित्सा क्षेत्र को बदलती चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को निरंतर अद्यतन करना होगा और समय विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री ने सैन्य नर्सिंग सेवा की नर्सों के योगदान की सराहना की।

चीन ने रूसी नागरिकों के वास्ते वीजा-मुक्त व्यवस्था को बढ़ाया

मास्को। चीन ने रूसी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इजवेस्टिया अखबार ने रूसी विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह खबर दी है। मंत्रालय ने अखबार को बताया कि हमारे साझेदारों ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि वे रूसी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था को एक और साल के लिए बढ़ाने को तैयार हैं। हम आपसी यात्रा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयार-तैयार करने हेतु उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

ग्राम के विकास के लिए समर्पित

फिरोज बेग

ग्राम प्रधान पद के युवा, शिक्षित व ईमानदार प्रत्याशी

ग्राम पंचायत रेहड़



आवश्यकता है

जामिया इस्लामिया अरबिया मुबारिया स्कूल, चरशावल रोड

(English Medium - कक्षा 1 से 5 तक)

विद्यालय हेतु एक योग्य एवं अनुभवी प्रधानाचार्य (Principal) तथा प्रशिक्षित अध्यापकों (Teachers) की आवश्यकता है।

प्रधानाचार्य के लिए योग्यता:

स्नातक/स्नातकोत्तर (शिक्षा में वरीयता) B.Ed

अध्यापक के लिए योग्यता:

स्नातक/स्नातकोत्तर (संबंधित विषय में) B.Ed/BTC

आकर्षक वेतन (योग्यता एवं अनुभव के अनुसार), अनुवासित एवं शैक्षणिक वातावरण

प्रवेश संबंधित सूचना: प्रवेश प्रारंभ (Admissions Open)

मासिक शुल्क: 50 रु. मात्र, प्रवेश नि:शुल्क (Free Admission)

स्थान: चरशावल रोड: इस्कु अन्वरुद्दीन अपना Resume शीघ्र भेजें या संपर्क करें।

M. : 9368215210

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीडी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवान कैप्सूल अफीम, चरस, डोडे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी इलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक

मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-941221108

श्री कृष्णा वोकेशनल एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज

गांधी कॉलोनी, मेन पवैण्डा रोड, निकट गऊशाला, मुजफ्फरनगर

प्रवेश सूचना-पैरामेडिकल/वोकेशनल एण्ड यूनियवर्सिटी कोर्स

10th व 12th (OPEN Board) से करें (विषय-साइंस, आर्ट, कॉमर्स etc.)

प्रवेश-10th हेतु- 8th पास/10th फेल, 12th हेतु-10th पास/12th फेल (Fresh, Part Admission & TOC Facility Available) (Exam-July व Oct 2026)

NIOS (शिक्षा मंत्रालय) कोर्स- D.N.V.S, Radiology (X-Ray Tech), CCH (एकोपेरिक), CAT (आधुनिक-पंचकर्म टैक), CHD (होम्योपैथिक), Diploma in Yoga & YTP, ECCE- (प्री-प्राइमरी शिक्षक हेतु), CCA (कम्प्यूटर), ET (डेलीक्टेंट टैक) ETC.

Contact us for UGC Approved University Courses:- Dip. in CMS&ED, Dip. in Panchakarma Therapy, OT Tech., DMLT, BMLT, BNYS, Optometry, Ophthalmic, Dental Tech & Hygiene, Radiology & Imaging Tech, Dietician and Nutritionist, Optician Dispensing, MPHW, MRT, Agriculture, Bachelor (All Paramedical) BBA, MBA, BSC, MSC, B.Com, M.Com, M.A. B.A. Polytechnic, ITI, Nursing Assitant Etc.

M.: 8505978850, 9634519104

ADMISSION OPEN

Mom & Me

NURTURING WITH LOVE

PLAY | NURSERY | LKG | UKG | 1st to 4th

M.: 9997023008

Branch1- New Mandi, Near Bala ji Dham Chowk

Branch2- Circular Road, Opp. Canara Bank

जो माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं और अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर होशियार और सफल बनाना चाहते हैं तो संपर्क करें!

Unique COACHING CENTRE

ESTD. 1995

UNIQUE SUCCESS POINT

पहले देखें! फिर विश्वास करें!

FREE 10 DAYS DEMO

आपकी एक मीटिंग हमारे साथ आपके बच्चों का जीवन बदल सकती है!

BOTH U.P. & C.B.S.E. BOARD STUDENTS CLASS 1 TO X

+91 7505612792 DIR- LOKESH CHAUHAN

+91 9412507193 M.Sc (Phy), B.Ed.